लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक :- BRLPS-LSBA/Proj/22/17/82 दिनांक :- 03.06.2017

प्रेषक

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार।

विषय :- **एस०बी०एम०जी० अन्तर्गत राशि की विमुक्ति के संबंध में।**

प्रसंग :- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के D.O.2/ 2/ SDWS/ 2017 दिनांक 29.05.2017 ।

महाशय,

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत राज्य को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु यह आवश्यक है कि शौचालय निर्माण एवं उपयोग के सम्बंध में समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर अधिक बल दिया जाय तथा इसे IEC (सूचना, शिक्षा एवं प्रसार) के प्रभावी उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा एस०बी०एम०जी० की राशि विमुक्ति प्रस्ताव में IEC पर व्यय, IHHL के Geo Tagging तथा शत् प्रतिशत सत्यापित ODF ग्रामों को सम्बद्ध किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कर्णांकित IEC मद (IEC-3.75%, CB-0.75%) का न्यूनतम 50% की राशि का उपयोग माह सितम्बर 2017 तक किया जाना है।

(ख) 02 अक्टूबर 2014 के उपरान्त बने शौचालयों में से न्यूनतम 80% शौचालयों का Geo Tagging कर लिया गया है।

(ग) स्व घोषित ODF ग्रामों की घोषणा के तीन माह के अन्दर शत् प्रतिशत सत्यापन कर लिया गया हो।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त Performance Indicator को राशि विमुक्ति प्रस्ताव से सम्बद्ध किए जाने के कारण जिले में प्राथमिकता के आधार पर IEC मद में व्यय, Geo Tagging एव ODF ग्रामों के सत्यापन के कार्य को सम्पन्न कराया जाय।

विश्वासभाजन,

3/06/17

(बालामुरुगन डी०)

अनुलग्नक:- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की छाया प्रति।

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

e-mail

Ecr- 41831/17

1

परमेश्वरन अय्यर
Parameswaran Iyer

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव का कार्यालय
30 MAY 2017
बिहार, पटना-800015

सचिव
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Secretary
Government of India
Ministry of Drinking Water & Sanitation
4th Floor, Pt Dindayal Antodaya Bhawan, N D-110003
Tel: 24361011, 24362715,
e-Mail: param.iyer@gov.in

OSD (AKS)

D.O. 2/2/S(dWS)/2017
29th May 2017

OSD AKS
SC-LSBA

Dear Anjani,

The Swachh Bharat Mission is at a unique juncture where changes related to collective behavior change and stopping the practice of defecation by building and using of toilets is unfolding in lakhs of villages across States. The State Governments are consequently making rapid strides towards the achievement of a Swachh Bharat.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोषांग
02 JUN 2017
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन

You will agree, however, that for more effective implementation and sustainability of the programme greater efforts needs to be made with respect to Information, Education and Communication (IEC) for behavior change. For this purpose, GoI has earmarked funds for IEC which need to be more optimally utilized. It is also important that when the status of the village is self-declared as ODF, it is verified within a period of 90 days as per the SBM(G) guidelines. We have also been repeatedly emphasizing the importance of the appropriate geo-tagging of toilets to ensure mapping of all assets created under the programme.

Accordingly, the following changes are being introduced to link the performance of States on key indicators and disbursement of the second instalment of SBM (G) funds to the States. The state should have:

1. Utilized 50% of 2017-2018 IEC funds by September 30, 2017 or by the time of release of second instalment
2. Geo tagged 80% of toilets constructed after 2nd October 2014; and
3. Verified all villages declared ODF within three months of self-declaration of ODF by villages.

मुख्य सचिव कार्यालय
आवती सं. 1840
दिनांक 31/5/17

To support States fast track progress on the above three items, the Ministry is separately issuing advisories and best practices. The Ministry would also soon convene a meeting with Principal Secretaries in charge of SBM(G) and officials concerned with the above to orient them on the way forward.

I request you to accord top most priority to the above eligibility indicators so that we can transfer the second instalment of funds to your State.

Regards

Yours sincerely,

Parameswaran Iyer

Shri Anjani Kumar Singh
Chief Secretary
Government of Bihar
Patna

SC, LSBA
Very important.
Pls. communicate the same to all DPMs/blocks for N/A.
2/6/17